कृषि नवाचार

ISSN: 3048-6092
https://www.krishinavachar.in
खण्ड 02 भाग 09 दिसम्बर, 2025

# कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए ई-नाम के लाभ

**वीणा राठौर [1*], किरण सोनी [2], नेहा द्विवेदी [3] और सेबिनसारा सोलोमन [4]**

[1]सहायक प्रोफ़ेसर, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, के.एन.के. उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर

[2]सहायक प्रोफ़ेसर, बागानी मसाला औषधीय और सगंध पौधा विभाग, के.एन.के. उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर

[3]सहायक प्रोफ़ेसर, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, इंदौर

[4]सहायक प्रोफ़ेसर, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, जेएनकेवीवी, जबलपुर

***E-mail: vrathore137@gmail.com**

लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (एसएफएसी) और केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम) को प्रायोजित किया, जो एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो 14 अप्रैल, 2016 को लाइव हुआ। सभी राष्ट्रीय कृषि बाजारों को संयोजित करने के लिए और कृषि वस्तुओं की कीमत की खोज के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन मंच बनाएं, एनएएम पोर्टल वर्तमान एपीएमसी ( कृषि उपज विपणन समिति (पीएमसी)/विनियमित विपणन समिति (आरएमसी) बाजार यार्ड, उप-बाजार यार्ड, निजी बाजार और अन्य अनियमित बाजारों से जुड़ता है। योजना मार्च 2018 तक 585 चयनित 1 विनियमित थोक कृषि बाजार यार्डों को एक एकीकृत ई-मार्केट प्लेटफॉर्म स्थापित करने का आह्वान किया गया। ई-एनएएम व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल का नाम होगा।

1. बाज़ारों को पहले राज्य स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत करना। एक एकीकृत ऑनलाइन बाजारमंच कृषि उत्पादों का उपयोग करके अखिल भारतीय व्यापार की अनुमति देना।
2. पूरे बोर्ड में विपणन और लेनदेन के तरीकों को मानकीकृत करना। यह सुनिश्चित करने के लिए बाज़ार कि वे कुशलतापूर्वक काम करें।
3. किसानों और डीलरों के लिए अधिक विपणन संभावनाएं प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पहुंच का उपयोग करना। खरीदारों/बाज़ारों की अधिक संख्या, किसान और खरीदार के बीच ज्ञान की विषमता को खत्म करना, कृषि-वस्तुओं की वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर बेहतर वास्तविक समय मूल्य की खोज, नीलामी प्रक्रिया में खुलापन और गुणवत्तापूर्ण उपज के अनुरूप मूल्य निर्धारण, ऑनलाइन भुगतान, और अन्य कारक जो विपणन प्रभावशीलता में योगदान करते हैं।
4. सूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए गुणवत्ता आश्वासन परख विधियों का निर्माण करना।
5. स्थिर कीमतों और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों तक उपभोक्ता की पहुंच को प्रोत्साहित करना।

## योजना घटक

1. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश एपीएमसी/आरएमसी का चयन परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा पूरा किया जाता है, जब पार्टियों ने योजना में उल्लिखित अपने एपीएमसी/आरएमसी अधिनियमों में अनिवार्य संशोधन पूरा कर लिया है और अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की मंजूरी प्राप्त कर ली है। पीएसी. प्रोग्रामिंग समर्थन के लिए पात्रता आवश्यकताएँ योजना नियमों में विस्तृत हैं।
2. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ई-एनएएम सॉफ्टवेयर का मुफ्त वितरण।
3. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को हार्डवेयर खरीद के लिए उनकी डीपीआर के आधार पर चयनित एपीएमसी/आरएमसी के लिए प्रति बाजार अधिकतम 30.00 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता मिलेगी। ई-एनएएम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण के लिए बाजार को तैयार करने के लिए, आपको एक इंटरनेट कनेक्शन, परख उपकरण और अन्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी। यदि प्रस्तावित बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्थापित करने के लिए किसी शेष निधि की आवश्यकता होती है, तो राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/उसकी एजेंसियां जिम्मेदार होंगी।

## सहायक प्रौद्योगिकी

ई-एनएएम के कार्यान्वयन के लिए, एसएफएसी, प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी ( एलआईए), रणनीतिक साझेदार ( एसपी) नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के माध्यम से प्रत्येक बाजार में एक वर्ष की अवधि के लिए एक मंडी विश्लेषक को निःशुल्क नियुक्त करेगी। लिमिटेड ( एनएएफसीएल), हितधारकों को दिन-प्रतिदिन सहायता प्रदान करने के लिए। यदि संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सुझाव दिया जाता है, तो निजी बाजारों तक ईएनएएम पोर्टल पहुंच को परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

ISSN: 3048-6092
https://www.krishinavachar.in
खण्ड 02 भाग 09 दिसम्बर, 2025

## क्षमता निर्माण

एक रणनीतिक साझेदार की मदद से, एपीएमसी/आरएमसी लाइन स्टाफ को उन्मुख किया जाएगा, और किसानों को मार्केट टॉक, ग्राम सभा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा।

## e-NAM के लिए कुछ आवश्यकताएं

कोई राज्य ई-एनएएम में "प्लग-इन" के लिए मंडियों का प्रस्ताव कर सकता है यदि वह तीन आवश्यक मानदंडों को पूरा करता है:

- मूल्य खोज के एक रूप के रूप में ई-नीलामी/इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को राज्य एपीएमसी अधिनियम में विशेष रूप से संबोधित किया जाना चाहिए।
- पूरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में वैध होने के लिए, एक ही ट्रेडिंग लाइसेंस होना चाहिए।
- एक राज्यव्यापी या केंद्रशासित प्रदेश-व्यापी बाज़ार शुल्क कर।

## विभिन्न एजेंसियों की भूमिका

स्ट्रैटेजिक पार्टनर (एसपी) छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (एसएफएसी) को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है, जो एनएएम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन, कृषि विपणन निदेशालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, रणनीतिक भागीदार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एसएएमबी), कृषि उपज विपणन समिति और विनियमित बाजार समिति (एपीएमसी/आरएमसी)।

## लाभ

1. ई-एनएएम के पूरी तरह लागू होने पर किसानों, मंडियों, व्यापारियों, खरीदारों, प्रोसेसर्स और निर्यातकों सभी को इससे लाभ होगा। उत्पादकों के लिए बेहतर और स्थिर मूल्य प्राप्ति के लिए हितधारकों को वास्तविक समय मूल्य खोज से लाभ होगा।
2. खरीदार लेनदेन पर पैसे बचाएंगे।
3. वस्तुओं की कीमतों की जानकारी ई-नाम स्मार्टफोन ऐप पर उपलब्ध हैएसएमएस का उपयोग बेची गई वस्तु की कीमत के साथ-साथ मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
4. बढ़ी हुई आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और गोदाम-आधारित बिक्री
5. किसानों के बैंक खातों से सीधे उनके ऑनलाइन खातों से डेबिट किया जाता है।

## भविष्य की संभावनाएं और हालिया ई-नाम विकास

ऑनलाइन ट्रेडिंग जो खुली है। वास्तविक समय में मूल्य की खोज। उत्पादकों के लिए उच्च कीमत की प्राप्ति। खरीदार की लेनदेन लागत कम है। उपभोक्ता निरंतर मूल्य निर्धारण और आपूर्ति भंडारण, रसद और गुणवत्ता प्रमाणन की उम्मीद कर सकते हैं। बढ़ी हुई आपूर्ति श्रृंखला दक्षता। गारंटीकृत भुगतान और वितरण। त्रुटियों के बिना लेनदेन की रिपोर्ट करना और बाजार पहुंच में सुधार, एमआईएस डैशबोर्ड, एक मोबाइल एप्लिकेशन, भुगतान क्षमताएं और ई-लर्निंग। शिकायत समाधान।

## ई-एनएएम को लागू करने में कुछ कठिनाइयाँ

कम विपणन योग्य अतिरिक्त. आवश्यक विशेषज्ञता वाले गुणवत्तापूर्ण कर्मचारियों को सुरक्षित रखें। ग्रेडिंग और परख के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है।

## निष्कर्ष

एक एकल ट्रेडिंग लाइसेंस, एक एकल बाज़ार बिंदु और एक इलेक्ट्रॉनिक नीलामी। नए नियमों के तहत ट्रेडिंग लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो गया है। खंडित जानकारी से छुटकारा कृषि वस्तुओं को निर्बाध रूप से स्थानांतरित किया जाता है, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होता है, और कम बर्बादी होती है, और किसानों को अधिक भुगतान किया जाता है। गुणवत्ता-आधारित सूचित प्रशिक्षण और गोदाम-आधारित बिक्री। किसानों और खरीदारों को उपलब्ध उपज, उसकी गुणवत्ता और बोली लगाने वाले बाजारों में दी जा रही कीमत के बारे में जानकारी देकर, इंटरनेट-आधारित e-NAM कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों और खरीदारों दोनों की सहायता करना है। e-NAM ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए, देश के किसानों का अनाज पारदर्शी तरीके से खरीदा और बेचा जाता है।